

G-secs यानी सरकारी प्रतभूतियों को ऋण देने और लेने का मसौदा मानदंड

प्रलिस के लिये:

सरकारी प्रतभूत ऋण दशा-नरिदेश- 2023, रेपो लेन-देन, राजकोषीय घाटा, खुला बाज़ार संचालन ।

मेन्स के लिये:

G-secs यानी सरकारी प्रतभूतियों को ऋण देने और लेने का मसौदा मानदंड ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रज़िर्व बैंक](#) ने भारतीय रज़िर्व बैंक ([सरकारी प्रतभूत ऋण](#)) नरिदेश- 2023 का मसौदा जारी कया ।

- भारतीय रज़िर्व बैंक ने सरकारी प्रतभूतियों (G-sec) में प्रतभूत ऋण देने और लेने की शुरुआत का प्रस्ताव कया है, जसका उद्देश्य नवशकों को नषिकरयि प्रतभूतियों को सकरयि करने तथा पोर्टफोलयो रटिरन बढ़ाने के लिये एक अवसर प्रदान करके प्रतभूत ऋण बाज़ार में व्यापक भागीदारी की सुवधा प्रदान करना है ।

मसौदा मानदंड:

- सरकारी प्रतभूत ऋण (GSL) लेन-देन न्यूनतम एक दिन और अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिये कये जाणगे ।
- ट्रेज़री बलियों को छोडकर केंद्र सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतभूतियाँ GSL लेन-देन के तहत ऋण देने/लेने के लिये पात्र होंगी ।
- केंद्र सरकार (ट्रेज़री बलि सहति) और राज्य सरकारों द्वारा जारी सरकारी प्रतभूतियाँ GSL लेन-देन के तहत संपारश्वकि के रूप में पात्र होंगी ।
- सरकारी प्रतभूतियों और रज़िर्व बैंक द्वारा अनुमोदति कसि भी अन्य इकाई में [रेपो लेन-देन](#) करने के लिये पात्र इकाई प्रतभूतियों के ऋणदाता के रूप में GSL लेन-देन में भाग ले सकेगी ।

सरकारी प्रतभूतियाँ:

- परचिय:
 - सरकारी प्रतभूत (G-Sec) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य लखित (Instrument) है ।
 - G-Sec एक प्रकार का ऋण साधन है जो सरकार द्वारा अपने [राजकोषीय घाटे](#) के वतितपोषण हेतु जनता से पैसा उधार लेने के लिये जारी कया जाता है ।
 - ऋण लेख एक वतितय साधन है जो जारीकर्त्ता द्वारा नरिदषिट तथिपर धारक को एक नश्चिति राशि, जसि मूलधन या अंकति मूल्य के रूप में जाना जाता है, का भुगतान करने के लिये संवदिात्मक दायतित्व का प्रतनिधितित्व करता है ।
 - यह सरकार के ऋण दायतित्व को स्वीकार करता है । ऐसी प्रतभूतियाँ अल्पावधि (आमतौर पर एक वर्ष से कम की मूल परपिक्वता अवधि के साथ वर्तमान में तीन अवधियों में जारी की जाती हैं, अरथात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन) या दीर्घ अवधि (आमतौर पर सरकारी बॉण्ड या दिनांकति प्रतभूतियाँ) एक वर्ष या उससे अधिक की मूल परपिक्वता अवधि वाली ट्रेज़री बलि कहलाती हैं ।
 - भारत में केंद्र सरकार ट्रेज़री बलि और बॉण्ड या दिनांकति प्रतभूतियाँ दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकति प्रतभूतियाँ जारी करती हैं, जनिहें राज्य वकिस ऋण (SDLs) कहा जाता है ।
 - G-Secs में व्यावहारिक रूप से डफिॉल्ट का कोई जोखमि नहीं होता है, इसलिये जोखमि मुक्त गलिट-एज इंस्ट्रूमंट कहलाते हैं ।
 - गलिट-एज सकियोरटिज़ उच्च-श्रेणी के नविश बॉण्ड हैं जो सरकारों और बड़े नगिमों द्वारा धन उधार लेने के साधन के रूप में पेश कये जाते हैं ।

G-Secs के प्रकार:

- ट्रेज़री बलि (T-बलि):

- ट्रेजरी बलि ज़िरो कूपन सक्रियोरटिज़ हैं और कोई ब्याज नहीं देते हैं। उन्हें छूट पर जारी किया जाता है और परपिक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है।
- **नकद प्रबंधन बलि (CMBs):**
 - वर्ष 2010 में भारत सरकार ने RBI के परामर्श से भारत सरकार के नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन के समाधान के लिये CMBs के रूप में जाना जाने वाला एक नया अल्पकालिक साधन पेश किया। CMBs में सामान्यतः T-बलि के समान विशेषताएँ होती हैं कति यह 91 दिनों से कम की परपिक्वता अवधि के लिये जारी किया जाता है।
- **डेटेड जी-सेक:**
 - डेटेड जी-सेक वे प्रतभूतियाँ हैं जिनका एक नशिचति या फ्लोटिंग कूपन (ब्याज दर) होता है, जिसका भुगतान अंकित मूल्य के साथ अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। डेटेड/ दिनांकित प्रतभूतियों की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है।
- **राज्य विकास ऋण (State Development Loans- SDL):**
 - राज्य सरकारें बाज़ार से भी ऋण प्राप्त कर सकती हैं, जिन्हें SDL कहा जाता है। SDL दिनांकित प्रतभूतियाँ हैं जो केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतभूतियों हेतु आयोजित नीलामी के समान एक नियमित नीलामी के माध्यम से जारी की जाती हैं।
- **जारी करने का तंत्र:**
 - RBI धन की आपूर्ति की स्थिति को समायोजित करने के हेतु जी-सेक की बिक्री या खरीद के लिये **खुला बाज़ार परचालन (Open Market Operations- OMO) आयोजित करता है।**
 - **RBI द्वारा सस्टिम से तरलता को हटाने हेतु जी-सेक की बिक्री की जाती है** और सस्टिम में तरलता बढ़ाने के लिये जी-सेक को वापस खरीदा जाता है।
 - **बैंकों को उधार देना जारी रखने की अनुमति देते हुए** मुद्रास्फीति को संतुलित करने हेतु इन कार्यों को अक्सर दैनिक आधार पर किया जाता है।
 - RBI वाणज्यिक बैंकों के माध्यम से खुला बाज़ार परचालन (OMO) आयोजित करता है और जनता के साथ सीधे व्यवहार नहीं करता है।
 - RBI सस्टिम में रुपए की मात्रा और कीमत को समायोजित करने हेतु **रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात तथा वैधानिक तरलता अनुपात** जैसे अन्य मौद्रिक नीति उपकरणों के साथ OMO का उपयोग करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 'खुला बाज़ार परचालन' कसि नरिदषिट करता है? (2013)

- अनुसूचति बैंकों द्वारा RBI से ऋण लेना
- वाणज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना
- RBI द्वारा सरकारी प्रतभूतियों का क्रय और वक्रय
- उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन-सा/से गैर-वत्तितिय ऋण में शामिल है/हैं? (2020)

- परिवारों का बकाया गृह ऋण
- क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि
- राजकोष बलि (Treasury bills)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- केवल 1
- केवल 1 और 2
- केवल 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

- ब्याज के साथ ऋण यानी मौद्रिक कर्ज़/उधार चुकाना संवदिात्मक दायतित्व है।
- **गैर-वत्तितिय ऋण:**
 - इसमें सरकारी संस्थाओं, परिवारों और व्यवसायों द्वारा जारी क्रेडिट उपकरण शामिल हैं जो कवित्तितिय क्षेत्र में शामिल नहीं हैं।
 - इसमें औद्योगिक अथवा वाणज्यिक कर्ज़, राजकोषीय बलि (ट्रेजरी बलि) और क्रेडिट कार्ड शेष (Balance) शामिल हैं।
 - वे बड़े पैमाने पर वत्तितिय ऋण के समान हैं, इस अपवाद के साथ कि गैर-वत्तितिय संस्थाएँ उन्हें जारी करती हैं। **अतः कथन 1, 2 और 3 सही हैं।**
- **अतः वकिलप (d) सही उत्तर है।**

प्रश्न. नमिन्लखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. भारतीय रज़िर्व बैंक भारत सरकार की प्रतभूतयिों का प्रबंधन और सेवाएँ प्रदान करता है, लेकनि कसिी राज्य सरकार की प्रतभूतयिों का नही ।
2. भारत सरकार कोष-पत्र (ट्रेज़री बलि) जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष-पत्र जारी नही करती ।
3. कोष-पत्र ऑफर अपने समतुल्य मूल्य से बट्टे पर जारी कयि जाते हैं ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

PDF Refernce URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/draft-norms-lending-and-borrowing-of-g-secs-i-e-government-securities>

